ALFAAZ TIMES

हर खबर, हर शहर

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION UNDER PROCESS
Application No. MAHMUL/2023/88574

GST GSTIN

UDYAM REGISTERED

DIGITAL NEWS NETWORK
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

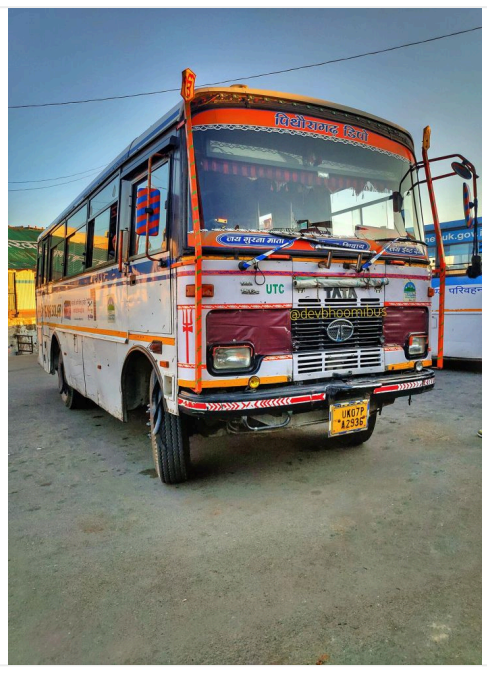
हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.alfaaztime.digital
info@alfaaztime.digital
+91
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

ऑटोमोबाइल

59 नई बसें जोड़ेंगी उटाराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बेड़ा



उटाराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपने बेड़े में 59 नई बसें जोड़ने की घोषणा की, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार हो सके। नई बसें मौजूदा मार्गों पर तैनात की जाएंगी, जिससे आवृत्ति बढ़ेगी और यात्रियों का इंतजार कम होगा। यह विस्तार राज्य के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। बेड़े के आकार को बढ़ाकर, UTC प्रमुख मार्गों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात जाम को कम करने की आशा रखता है।

धर्म

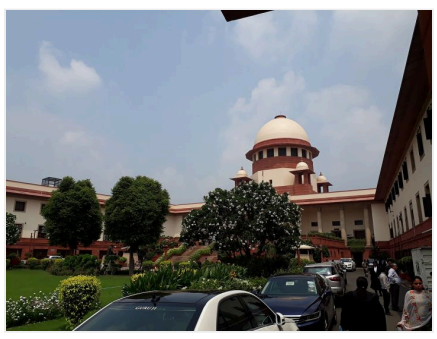
उत्तराखण्ड में कार गॉर्ज में गिरने से गुजरात के पाँच भक्त मारे गए



उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्ग पर गुजराती भक्तों के सात सदस्यों को ले जा रही कार नियंत्रण खोकर गॉर्ज में गिर गई, जिससे पाँच लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने दुर्घटना की सूचना प्राप्त कर तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। जिला प्रशासन और राज्य पुलिस की बचाव टीमों ने मलबे से बचे लोगों को बाहर निकाला। दो जीवित बचे गंभीर रूप से घायल रहे और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और तीर्थयात्रियों को पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सतर्क रहने की चेतावनी दी है।

नौकरी

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के 'पे माइनस पेंशन' नियम को बरकरार रखा



एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया "पे माइनस पेंशन" नियम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू रहेगा। यह निर्णय उन कई याचिकाओं को समाप्त करता है, जिन्होंने इस योजना को संवैधानिक और वित्तीय दृष्टिकोण से चुनौती दी थी।

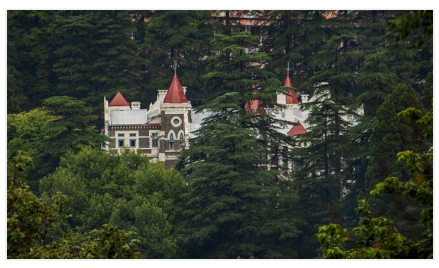
इस नियम के तहत, यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी फिर से सरकारी वेतनभोगी पद पर नियुक्त होता है, तो उसकी पेंशन को वेतन से घटा दिया जाता है, जिससे कुल आय मूल वेतन स्तर से अधिक न हो। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह उपाय सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन अधिकारों को कमजोर करता है। विचाराधीन बेंच ने कहा कि यह नियम दोहरी लाभप्राप्ति को रोकने के लिए एक वैध वित्तीय उपाय है और किसी भी संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं करता। इसने यह भी रेखांकित किया कि पेंशन की स्थिरता और रोजगार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का अधिकार सरकार को है।

इस फैसले का अर्थ है कि कई हजारों पूर्व अधिकारी जो अनुबंध या अस्थायी पदों पर कार्यरत होते हैं, उनकी पेंशन उसी अनुसार घटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य की पेंशन सुधारों को आकार देगा और सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बाद के रोजगार प्रबंधन को प्रभावित करेगा।

सरकारी अधिकारियों ने इस परिणाम का स्वागत वित्तीय सतर्कता के कदम के रूप में किया, जबकि कई पेंशनधारक संगठनों ने निराशा व्यक्त की और आगे कानूनी उपायों की संभावना जताई।

स्थानीय

उत्तarakhand हाई कोर्ट ने सार्वजनिक पार्कों का ऑडिट आदेश दिया, नौ महीने की समय सीमा तय



उत्तarakhand हाई कोर्ट ने देहरादून में सुनवाई के दौरान यह बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक पार्कों की वैधानिक सूची तैयार करने में देरी की है, जो उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण अधिनियम के तहत अनिवार्य है। कोर्ट ने इस चूक को क़ानूनी दायित्व का उल्लंघन और शहरी हरित क्षेत्रों की योजना में बाधा बताया।

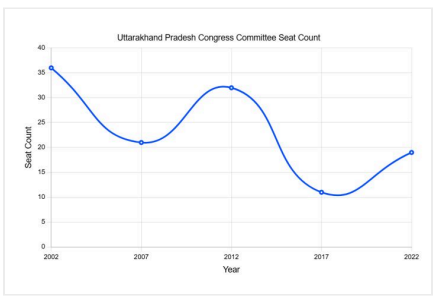
आदेश में विभागीय वन विभाग और शहरी विकास प्राधिकरण को राज्य भर के सभी सार्वजनिक पार्कों का समन्वित सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इस सर्वेक्षण में प्रत्येक पार्क की कानूनी स्थिति, क्षेत्रफल, सुविधाएँ और रख-रखाव मानकों की जाँच शामिल होगी।

कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की है और आदेश जारी करने की तिथि से नौ महीने के भीतर पूरी ऑडिट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया है। अनुपालन न करने पर अदालत में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने, हरित क्षेत्रों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने और भविष्य की शहरी योजना में सहायक होने की आशा रखता है।

राज्य के अधिकारियों ने आदेश को स्वीकार किया और सहयोग का आश्वासन दिया, यह कहा कि तुरंत एक कार्यबल गठित किया जाएगा ताकि यह कार्य शुरू किया जा सके। पर्यावरण संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया, इसे राज्य की प्राकृतिक संपदा के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना।

राजनीति

उत्तराखंड कांग्रेस दल ने जमीन आवंटन की समस्याओं पर उठाया मुद्दा



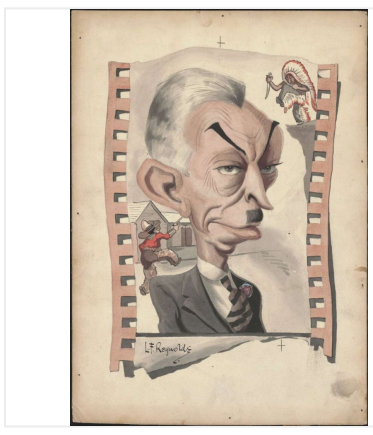
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तराखंड इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल ने जमीन आवंटन से जुड़ी विशेष चिंताओं को प्रकाश में लाया है। इस दल ने इन मुद्दों को औपचारिक रूप से उठाया है, जिसमें वितरण प्रक्रिया में स्पष्टता और समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

अद्यतन रिपोर्ट में दल ने विस्तृत विवरण प्रदान नहीं किए, लेकिन ध्यान राज्य में जमीन आवंटन की प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक पहलुओं पर केंद्रित है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जमीन आवंटन प्रक्रिया के न्यायसंगत और पारदर्शी दिशानिर्देशों का पालन कराना है।

यह कदम पार्टी के स्थानीय शासन मुद्दों में सक्रिय संलग्नता और उत्तराखंड में अपने मतदाताओं की शिकायतों को दूर करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दल के इस हस्तक्षेप से क्षेत्र में जमीन आवंटन नीतियों की वर्तमान स्थिति पर और चर्चा होने की उम्मीद है।

अपराध

गंगा में मिला उत्तर प्रदेश का व्यवसायी, मिला सुसाइड नोट



ऋषिकेश में गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी का शव बरामद हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने उसे पहचाना। पुलिस ने बताया कि एक सुसाइड नोट मिला है, जिसे व्यवसायी ने अपने रिसॉर्ट के कर्मचारियों को लिखा था। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

स्थानीय

बासंती देवी: काशी नदी को बचाने वाली उत्तराखंड की महिला



उत्तराखंड की निवासी बासंती देवी को काशी नदी को संरक्षित करने में मदद करने के लिए श्रेय दिया गया है, जो एक जलधारा है जिसे स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ के जोखिम के कारण लंबे समय से चिंता का विषय माना जाता है।

उनका योगदान उस समय आया जब नदी के स्वास्थ्य और आसपास के गांवों की सुरक्षा खतरे में थी। नदी संरक्षण के उद्देश्य से सामुदायिक पहलों में भाग लेकर, देवी ने बाढ़ जोखिम को कम करने और नदी के पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित रखने के प्रयासों में योगदान दिया। उनके कार्यों का प्रभाव पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया है, जहाँ स्थानीय अधिकारियों ने नदी की लचीलापन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कैसे व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण का समर्थन कर सकती है।

हालाँकि उनके द्वारा समर्थित परियोजनाओं का पूरा दायरा अभी भी समीक्षा के तहत है, बासंती देवी की समर्पण को पहले ही निवासियों और अधिकारियों के बीच काशी नदी की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए मान्यता मिली है।

देश

उत्तराखंड के छह बच्चों को राज्य बाल साहसिता पुरस्कार से सम्मानित



उत्तराखंड सरकार ने राज्य के छह युवा निवासियों को राज्य बाल साहसिता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उनके असाधारण साहस और कठिन परिस्थितियों में लिए गए त्वरित निर्णयों को मान्यता देता है।

यह पुरस्कार एक राज्य स्तरीय पहचान है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों के साहस को उजागर करना है जिन्होंने निस्वार्थता से कार्य किया है। इन व्यक्तियों को सम्मानित करके, प्रशासन युवा पीढ़ी के लिए साहस और जिम्मेदारी का एक उदाहरण पेश करना चाहता है।

अगर उनके चयन के कारण बनने वाले घटनाक्रम की विशिष्ट विवरण प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्तार से नहीं दिए गए, तो भी इन छह बच्चों द्वारा प्रदर्शित प्रशंसनीय भावना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह समारोह राज्य की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जो अपने युवाओं के साहसिक कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने की है।

राजनीति

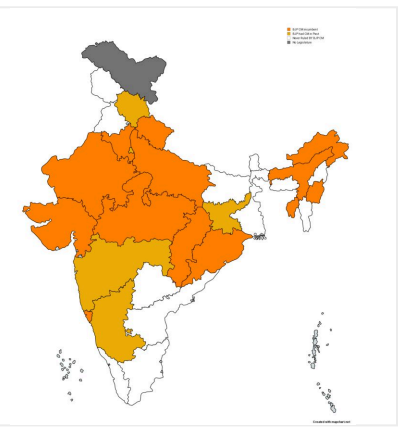
शाह: उत्तराखंड ने बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक कोड का मार्ग प्रशस्त किया



घर मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में हाल ही में लागू समान नागरिक कोड अन्य बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल होगा। शाह ने उत्तराखंड की इस पहल में अग्रणी भूमिका निभाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक कोड की सफलता से अन्य राज्यों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित होगा।

राजनीति

उत्तराखंड में BJP की रणनीति: हटाए गए मतदाताओं को वापस लाना, गटबंदी पर रोक



भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उत्तराखंड में अपनी कार्यवाही के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका तैयार की है, जिसमें क्षेत्र की राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित किया गया है। पार्टी का मुख्य ध्यान निर्वाचन सूची में सुधार पर केंद्रित है, विशेष रूप से उन मतदाताओं को पुनर्स्थापित करने पर जो पहले सूचियों से हटा दिए गए थे।

यह कदम इसका उद्देश्य है कि सभी पात्र मतदाता अगले चुनाव चक्र में अपनी भूमिका निभा सकें। पार्टी चाहती है कि जो मतदाता गलती से या जानबूझकर डेटाबेस से हटाए गए थे, उन्हें वापस लाया जाए ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी का प्रभाव मजबूत हो सके।

इसके अलावा, बीजेपी अपनी राज्य इकाई के भीतर गटबंदी को कम करने पर जोर दे रही है। पार्टी नेतृत्व आंतरिक मतभेदों को दूर करने और संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो पिछले कुछ समय से पार्टी की कमजोरी का कारण बन रहा था।

यह रणनीति उत्तराखंड में पार्टी की आधारशिला को मजबूत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें मतदाता डेटा में प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ संगठनात्मक सुधारों पर भी बल दिया गया है।

राजनीति

धामी: बंदी छोड़ दिवस मानवता की आजादी का प्रतीक है



उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंदी छोड़ दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसे उन्होंने मानवता की आजादी का एक गहरा प्रतीक बताया है। अमृतसर से जारी एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कानूनी और सामाजिक ढांचे में करुणा और न्याय के महत्व पर जोर दिया।

इन टिप्पणियों से सरकार की पुनर्वास और कारावास के मानवाधिकारों के पहलू पर अपनी दृष्टि स्पष्ट होती है। इस दिन को स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में प्रस्तुत करके, नेतृत्व क्षमा और दूसरे मौके के विस्तृत सामाजिक मूल्यों पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है।

मुख्यमंत्री के इन शब्दों ने अपराध न्याय सुधार और कारागार प्रणाली में व्यक्तियों के मानवीय व्यवहार के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर चल रही चर्चा से मेल खाया है। इन टिप्पणियों से न्याय प्रशासन से जुड़े नैतिक दायित्वों की याद दिलाई गई है।

राजनीति

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 'श्रीमत् एक्सप्रेस' समाचार पत्र पर प्रतिबंध रोक दिया



उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 'श्रीमत् एक्सप्रेस' समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने और संपादक को प्रिंट मीडिया से हटाने के प्रस्ताव को रोकने के लिए एक स्टे ऑर्डर जारी किया है। यह फैसला समाचार पत्र और उसके संपादक द्वारा दायर की गई कानूनी चुनौती के जवाब में आया है। ब्लैकलिस्टिंग के पीछे के विशिष्ट कारण सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किए गए हैं। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर ब्लैकलिस्टिंग के कार्यान्वयन को तब तक रोकता है जब तक कि आगे के कानूनी प्रक्रियाएं पूरी न हो जाएं।

अपराध

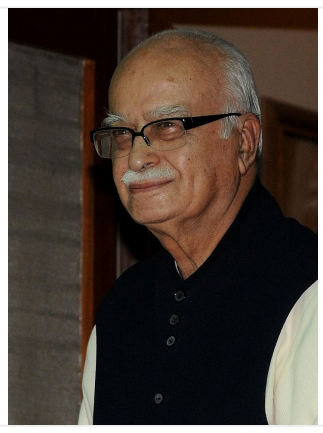
उत्तarakhand मंत्री रेखा आर्य के पति पर हमला शिकायत के बाद गिरफ्तार



उत्तarakhand पुलिस ने राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति को उनके खिलाफ दर्ज हुई हमला शिकायत के बाद हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई शिकायत दर्ज होने के कुछ ही दिनों बाद की गई, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। घटना के विवरण या शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है। मंत्री ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। मामला सामान्य आपराधिक जांच प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।

राजनीति

भारत रत्न एल.के. अग्रवानी का 100वां जन्मदिन: भारतीय राजनीति की एक मील का पत्थर



एल.के. अग्रवानी, पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता, आज 100 वर्ष के हो गए, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस शताब्दी को देश के राजनीतिक नेताओं ने स्वीकार किया, जिन्होंने उनकी लंबी सेवा और नेतृत्व को उजागर किया। अग्रवानी भाजपा के विचारधारा को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं और दशकों से राष्ट्रीय नीति चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका 100वां जन्मदिन उनके स्थायी विरासत और साथियों व जनता के बीच उनके सम्मान का प्रतीक है।

स्थानीय

अमर उजाला ने जारी किया अल्मोरा शहर का दैनिक समाचार बुलेटिन



अमर उजाला ने हाल ही में अल्मोरा शहर पर केंद्रित अपनी दैनिक बुलेटिन जारी की है। इस प्रकाशन में स्थानीय विकास, कार्यक्रम और समुदाय की कहानियाँ शामिल हैं जो निवासियों के लिए प्रासंगिक हैं। यह बुलेटिन अमर उजाला के प्रयास का हिस्सा है ताकि अल्मोरा के लोगों को स्थानीय मामलों से अवगत कराया जा सके। पाठक पूर्ण संस्करण अमर उजाला की वेबसाइट या प्रिंट में प्राप्त कर सकते हैं।

राजनीति

गोदीयल ने शाह के दौरे का विरोध काले बैंड पहनकर किया



गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें गोदीय नामक एक विरोधकर्ता ने काले बैंड पहनकर विरोध जताया। गोदीय के विरोध का स्वरूप और उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। विरोध के स्थान और संदर्भ के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

देश

उत्तराखंड पुलिस को मिला राष्ट्रपति पुलिस रंग



राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो राज्य पुलिस बल को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है। उत्तराखंड पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध से निपटने और राज्य के नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रशंसनीय कार्य के लिए मान्यता प्राप्त है। पुरस्कार समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जहाँ भारत के राष्ट्रपति उत्तराखंड पुलिस को औपचारिक रूप से रंग प्रदान करेंगे।

राजनीति

अमित शाह ने उत्तराखंड में बीजेपी के लिए 65 सीट का लक्ष्य रखा



बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर दिया और तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान किया। शाह का 65 सीटों का लक्ष्य राज्य विधानसभा पर बीजेपी के नियंत्रण को बरकरार रखने की अपनी क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।